पावर मशीन्स इंडिया लिमिटेड

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य और अन्य

(सिविल अपील संख्या 5317/2017)

अप्रैल 17,2017

[अरुण मिश्रा और एस. अब्दुल नजीर, जे. जे.]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 धारा. 18, 21(3), 30 - उद्यम सुविधा परिषद नियम, 2006 आर. 5 - मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 - धारा 36 (1)-2006 अधिनियम के तहत मध्यस्थता पुरस्कार पारित किया गया, जिसमें अपीलकर्ता को प्रतिवादी संख्या 3 को दी गई राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है-अपीलकर्ता की याचिका कि 2006 के नियमों की धारा 5 जिसमें उस राशि की वसूली का प्रावधान है जिसके लिए 2006 अधिनियम की धारा 18(3) के तहत मध्यस्थता पुरस्कार पारित किया गया है, क्योंकि भूमि राजस्व का बकाया अधिकार से बाहर है और 1996 अधिनियम की धारा 36(1) के प्रतिकूल भी है, क्योंकि एक बार सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को धारा 36, 1996 अधिनियम को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया था। सी. पी. सी. का आदेश 21 एक डिक्री के रूप में, लेकिन ऐसे उपचार प्रदान करने के मामले में, विभिन्न उपायों को कानून बनाने के लिए खुला है जो असंगत हो सकते हैं-राशि की वसूली के लिए एक उपाय का चुनाव पुरस्कार धारक की पसंद पर निर्भर करेगाः- निर्णय देनदार के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं है-यह एक उपाय चुनने का सवाल है-यह व्यक्ति के लिए उनमें से एक का चुनाव करना है और ऐसा उपाय प्रदान करने में तिरस्कार का कोई सवाल नहीं है-सिविल प्रक्रिया संहिता एकमात्र उपाय नहीं हो सकता है और यह सिविल कोर्ट के हस्तक्षेप के बिना वसूली तंत्र

को कानून बनाने के लिए खुला है-नियम 5 को त्वरित वसूली सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए उचित रूप से अधिनियमित किया गया है कि छोटे, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को अपीलकर्ता की याचिका का सामना न करना पड़े कि आर. 5 असंगत और प्रतिकूल है

उपाय-बहुवचन उपचार-वैधताः उपचारात्मक वैधानिक प्रावधानों के मामले में, उपचारों की बहुलता हमेशा प्रदान की जा सकती है, भले ही वे असंगत हों-हालाँकि, केवल एक ही उपाय चुनना पड़ता है-यह व्यक्ति के लिए है कि वह उनमें से एक का चयन करे और इस तरह के उपचार प्रदान करने में अस्वीकृति का कोई सवाल ही नहीं है।

अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1. नियम 5, उद्यम सुविधा परिषद नियम, 2006 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 30 के तहत नियम बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए बनाया गया है। अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए 2006 के नियमों के नियम 5 के तहत त्वरित वसूली तंत्र प्रदान किया गया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि मध्यस्थता पुरस्कार में दी गई राशि को भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है। [पैरा 9,10 और 13) (562-बी; 565-सी]

1.2 दूसरी ओर मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 36 में प्रावधान है कि एक बार 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने के लिए आवेदन दायर करने का समय समाप्त हो जाने के बाद, इसे सी. पी. सी. के प्रावधानों के अनुसार लागू किया जाएगा जैसे कि यह अदालत की डिक्री हो। [पैरा 11) (564-बी]

1.3 इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2006 के नियमों का नियम 5 1996 के अधिनियम की धारा 36 (1) में निहित प्रावधानों के साथ असंगत है जो सी. पी. सी. के आदेश 21 के तहत एक डिक्री के रूप में वसूली तंत्र प्रदान करता है, लेकिन ऐसे उपचार प्रदान करने के मामले में, यह विभिन्न उपायों को कानून बनाने के लिए खुला है जो असंगत हो सकते हैं। यह एक उपाय चुनने का सवाल है। राशि की वसूली के लिए एक उपाय का चुनाव पुरस्कार धारक की पसंद पर निर्भर करेगा। 1996 के अधिनियम की धारा 36 के साथ-साथ 2006 के नियमों के नियम 5 दोनों प्रावधानों का उद्देश्य अलग-अलग प्रक्रियाओं द्वारा राशि की वसूली करना है। प्रावधानों की मंशा समान है। निर्णय देनदार के प्रति कोई पूर्वाग्रह पैदा होने का कोई सवाल ही नहीं है। बहुवचन उपचार प्रदान करना तब मान्य होता है जब किसी व्यक्ति के लिए दो या दो से अधिक उपचार उपलब्ध होते हैं, भले ही वे असंगत हों, वे मान्य होते हैं। उनमें से किसी एक को चुनना व्यक्ति का काम है और इस तरह का उपाय प्रदान करने में तिरस्कार का कोई सवाल ही नहीं है। सिविल प्रक्रिया संहिता एकमात्र उपाय नहीं हो सकता है। यह दीवानी न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना वसूली तंत्र को कानून बनाने के लिए खुला है। [पैरा 13,14 और 17) [565-डी-ई; 566-एफ; 569-सीजे

1.4 इसमें कोई संदेह नहीं है कि सी. पी. सी. के तहत एक डिक्री के निष्पादन के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया प्रदान की गई है, लेकिन अब तक यह सर्वविदित है कि एक डिक्री प्राप्त करने के बाद, बेईमान निर्णय देनदारों द्वारा प्रावधानों के दुरुपयोग के कारण इसका त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करना अधिक कठिन हो गया है, जिसकी कभी परिकल्पना नहीं की गई थी। इस प्रकार, भूमि राजस्व के बकाया के रूप में त्वरित वसूली प्रदान करना, वास्तव में, आज की आवश्यकता थी और नियम 5 को त्वरित वसूली सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि छोटे, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को नुकसान न हो, सही ढंग से लागू किया गया है। इस निवेदन में कोई बल

नहीं है कि भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली प्रक्रिया कठोर है। यह काफी उचित है और देय राशियों की वसूली के लिए विभिन्न अधिनियमों में प्रदान किया गया है। इस प्रक्रिया को किसी भी तरह से अवैध, मनमाना, कठिन या कठोर नहीं कहा जा सकता है। [पारस 18,19] [569-ई-जी]

1.5 तत्काल मामले में धारा 30 के तहत प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करके, 2006 के अधिनियम के उद्देश्य की रक्षा की जा रही है। नियम का उद्देश्य उद्देश्य को लागू करना है। यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिकार को पार कर दिया गया है और न ही यह कहा जा सकता है कि नियम बनाने की शक्ति की आड़ में अधिनियम का दायरा बढ़ाया या संकुचित किया गया है। दोनों प्रावधानों का उद्देश्य वसूली सुनिश्चित करना है। नियमों का नियम 5 एक उपचारात्मक प्रावधान होने के कारण सहायक है। यह अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त त्वरित उपचार प्रदान करने के लिए खुला है। [पैरा 20,21] [571-ई; 572-एफ]

1.6 नियमों के नियम 5 के तहत परिकल्पित भूमि राजस्व की वसूली की प्रक्रिया को भेदभावपूर्ण नहीं कहा जा सकता है, यह काफी उचित प्रक्रिया है। इसे कठोर या कठोर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह काफी उचित प्रक्रिया है और यह अधिनियम के अधिदेश को आगे बढ़ाती है। नियम 5 के निष्पादन की प्रक्रिया और सी. पी. सी. के बीच के अंतर को अनुचित नहीं कहा जा सकता है ताकि भेदभाव की बुराई को आकर्षित किया जा सके। [पैरा 28] [576-डी)

बी. के. श्रीनिवासन और अन्य। v. कर्नाटक राज्य और अन्य। (1987) 1 एस. सी. सी. 658: [1987) 1 एस. सी. आर. 1054; पोषण सुधार और अन्य की अकादमी। v. भारत संघ आदि। (2011) 8 एस. सी. सी. 274: [2011) 8 एस. सी. आर. 680; जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ और ए. एन. आर. v. डॉ. सुभाष चंद्र यादव और

अन्र। (1988) 2 एस. सी. सी. 351: (1988) 3 एस. सी. आर. 62; श्री मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड, मदुरै आदि। बनाम श्री ए. वी. विश्वनाथ शास्त्री और आमः ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 13: (1955) एस. सी. आर. 787-विशिष्ट

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण बनाम के. डी. बाली और अन्र। (1988) 2 एस. सी. सी. 360: (1988) 3 एस. सी. आर. 370; अविंदर सिंह और अन्य। v. पंजाब राज्य और अन्य। (1979) 1 एस. सी. सी. 137: (1979) 1 एस. सी. आर. 845; सूरज मॉल मोहता एंड कंपनी बनाम ए. वी. विश्वनाथ शास्त्री एंड एमः [1955) 1 एस. सी. आर. 448-लागू नहीं है।

बिहार राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड बनाम उमा शंकर शरण और अन्र। (1992) 4 एस. सी. सी. 196: [1992) 3 एस. सी. आर. 892; मार्डिया केमिकल्स लिमिटेड और अन्य। बनाम भारत संघ (2004) 4 एस. सी. सी. 311: [2004) 3 एस. सी. आर. 982-पर निर्भर था।

कृषि बाजार समिति बनाम शालीमार केमिकल वर्क्स लिमिटेड (1997) 5 एस. सी. सी. 516: [1997) 1 पूरक। एस. सी. आर. 164; डॉ. महाचंद्र प्रसाद सिंह बनाम अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद और अन्य। (2004) 8 एस. सी. सी. 747: (2004) 5 पूरक। एस. सी. आर. 692; मगनलाल छगनलाल (पी) लिमिटेड बनाम ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम और अन्य। (1974) 2 एस. सी. सी. 402: [1975) 1 एस. सी. आर. 1-संदर्भित।

"न्यायमूर्ति जी. पी. द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत। सिंह, 14 'एच एडन-पर भरोसा किया

मामला विधि संदर्भ

(1992) 3 एस. सी. आर. 892 पैरा 14 (2004) 3 एस. सी. आर. 982 पैरा 17 (1997) 1 पूरक पर निर्भर था। एस. सी. आर. 164 पैरा 20 (2004) 5 सप्लीमेंट को संदर्भित करता है। पैरा 21 (1987) 1 एस. सी. आर. 1054 विशिष्ट पैरा 22 (2011) 8 एस. सी. आर. 680 विशिष्ट पैरा 23 (1988) 3 एस. सी. आर. 62 विशिष्ट पैरा 24 (1988) 3 एस. सी. आर. 370 अप्रयोज्य पैरा 25

[1979] 1 लागू न होने वाला पैरा 25 (1955) 1 एस. सी. आर. 448 लागू न होने वाला पैरा 26 [1955] एस. सी. आर. 787 विशिष्ट पैरा 27 [1975] 1 एस. सी. आर. 1 पैरा 28 को संदर्भित करता है।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 5317/2017

2016 की रिट याचिका संख्या 11824 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 18.07.2016 के निर्णय और आदेश से।

पी. चिदंबरम, अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता, असीम सूद, मयंक पांडे, एन. भागवतुला, ध्रुव सूद, एन. वोहरा, सुश्री माधवी खन्ना, अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता।

अर्जुन गर्ग, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय अरुण मिश्रा, जे. द्वारा दिया गया था।

1. अनुमति प्रदान की गई

2. यह अपील अपीलार्थी-पावर मशीन्स इंडिया लिमिटेड द्वारा की गई है, जो जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के निर्णय और आदेश से व्यथित है, जिससे अपीलार्थी द्वारा मध्य प्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद नियम, 2006 (इसके बाद "नियम" के रूप में संदर्भित) के नियम 5 को अधिकार से बाहर घोषित करने के लिए दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया है, जिसे

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (इसके बाद "2006 के अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 21 (3) के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए तैयार किया गया था। नियम 5 उस राशि की वसूली का प्रावधान करता है जिसके लिए 2006 के अधिनियम की धारा 18 (3) के तहत भूमि राजस्व के बकाया के रूप में अधिनिर्णय पारित किया जाता है, जिससे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 36 (1) में प्रदान की गई राशि की वसूली के लिए अतिरिक्त उपाय प्रदान किया जाता है

3. यह उल्लेख करना उचित है कि पुरस्कार 2006 के अधिनियम के तहत पारित किया गया था जिसके द्वारा अपीलार्थी को प्रतिवादी संख्या 3 यानी लक्ष्मी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज (भोपाल) प्राइवेट लिमिटेड को सम्मानित राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। यह पुरस्कार मध्य प्रदेश सुविधा परिषद द्वारा रुपये 1,15,77,630/- के साथ-साथ रुपये 1,04,96,746/- की राशि के साथ 10.1.2013 तक के ब्याज के लिए पारित किया गया था। ब्याज की वास्तविक राशि का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर का तीन गुना था जिसका भुगतान पुरस्कार के 30 दिनों के भीतर किया जाना था। यह पुरस्कार 15.1.2014 पर पारित किया गया था।

4. कलेक्टर, नोएडा ने नियमों के तहत मध्य प्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद द्वारा जारी किए गए पत्र दिनांक 2.4.2016 के अनुसार राशि की वसूली शुरू की। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के तहत कथित रूप से 20.4.2016 पर अपीलार्थी को वसूली प्रशस्ति पत्र दिया गया था। अपीलार्थी द्वारा एक अन्य प्रशस्ति पत्र 16.5.2016 पर प्राप्त किया गया था जो 20.4.2016 पर जारी किया गया था। इसके बाद, अपीलार्थी ने वसूली की कार्यवाही को रद्द करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की।

हालाँकि, दादरी के तहसीलदार, गौतम बुद्ध नगर ने 23.5.2016 पर वसूली प्रशस्ति पत्र के अनुसार आईसीआईसीआई बैंक के साथ अपीलार्थी के बैंक खाते से एक राशि of Rs.1,18,78,588.14 निकाली। 24.5.2016 पर, अपीलार्थी द्वारा यह अनुमान लगाया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक में अपीलार्थियों के बैंक खाते से रुपये. 2,12,33,618.57-डी की अतिरिक्त राशि बरामद की गई थी। अपीलार्थी ने नियम 5 को अधिकार से बाहर घोषित करने के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 2016 की रिट याचिका [सी. जे. आई. डी. 1] दायर की। अपीलार्थी ने एक और डब्ल्यू. पी. दायर की। [वसूली कार्यवाही को इस आधार पर रद्द करने के लिए कि वसूली नियम 5 के अनुपालन में नहीं थी, 2016 का सी. जे. <आई. डी. 1। नियम पर सवाल उठाने वाली उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था। 2016 की रिट याचिका [सी] No.12127 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी और इसने प्रतिवादी संख्या 3 को नियम डी नोवा के तहत और कानून के अनुसार वसूली कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दी थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर याचिका को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए खारिज कर दिया गया था कि उपरोक्त रिट याचिका को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी

5. तहसीलदार, दादरी ने नियम 5 के तहत वसूली of Rs.5,29,58,937 के लिए नई वसूली कार्यवाही जारी की-जैसा कि दिनांक 15.1.2014 के पुरस्कार के अनुसार है। याचिकाकर्ता को 19.9.2016 पर ताजा वसूली प्रशस्ति पत्र दिया गया था। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश में कहा है कि नियम 5 अधिकार से बाहर नहीं है और 2006 के अधिनियम के सख्त अनुरूप है। इससे व्यथित होकर, अपील को प्राथमिकता दी गई है।

6. अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पी. चिदम्बरम और डॉ. ए. एम. सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि नियम 5 भारत के संविधान के

अनुच्छेद 14 का अधिकार से परे, मनमाना और उल्लंघनकारी है और 2006 के अधिनियम की धारा 18 में निहित प्रावधानों के साथ पठित 1996 के अधिनियम की धारा 36 में निहित प्रावधानों के प्रतिकूल है। यह 2006 के अधिनियम की धारा 21 और 30 के तहत प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति से परे है। एक बार सिविल प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में, 'सी. पी. सी.') के प्रावधानों को लागू कर दिए जाने के बाद, वसूली केवल सी. पी. सी. के आदेश 21 के तहत शुरू की जा सकती थी जो निर्णय देनदार को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है। सी. पी. सी. के आदेश 21 नियम 22 में प्रावधान है कि यदि दो साल से अधिक समय के बाद निष्पादन किया जाता है, तो देरी की व्याख्या की जानी चाहिए। अदालत के पास सी. पी. सी. के आदेश 21 नियम 26 के तहत निष्पादन पर रोक लगाने की शक्ति है। सी. पी. सी. के आदेश 21 नियम 58 में संपत्ति की कुर्की पर आपत्ति का प्रावधान है और आपत्तियों के निर्णय के लिए आदेश 21 के तहत प्रक्रिया प्रदान की गई है। यदि आपत्ति पर विचार नहीं किया जाता है, तो सी. पी. सी. के आदेश 21 नियम 58 (1) में दिए गए अनुसार मुकदमा दायर करने का अधिकार है। यदि आवश्यक हो तो बिक्री के संबंध में सी. पी. सी. के आदेश 21 नियम 66,69,89 और 92 के तहत विस्तृत प्रक्रिया प्रदान की जाती है। नियमों के नियम 5 के तहत प्रदान किए गए उपाय में उपरोक्त सुरक्षा उपाय शामिल नहीं हैं और राशि को भूमि राजस्व के बकाया के रूप में ठीक से वसूल किया जा सकता है। इस प्रकार, नियम 5 के तहत उपाय कठोर है और इसलिए इसका सहारा नहीं लिया जा सकता था। अपीलार्थियों की ओर से यह भी पुरजोर आग्रह किया गया कि केवल चार राज्यों, यानी पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा और आंध्र प्रदेश में 1996 के अधिनियम की धारा 36 के तहत प्रदान किए गए सी. पी. सी. के अनुसार वसूली की जाए। इस प्रकार, चारों राज्यों द्वारा एक भेदभावपूर्ण प्रावधान किया गया है जो काफी

मनमाना और अस्वीकार्य है। केंद्रीय कानून में जो निहित है, उसके अपमान में राज्य कोई प्रावधान लागू नहीं कर सकते थे।

7. प्रत्यर्थियों की ओर से यह तर्क दिया गया कि नियम 2006 के अधिनियम की धारा 30 के दायरे में बनाया गया है। यह अधिनियम के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए शीघ्र वसूली प्रदान करने के लिए है। 2006 के अधिनियम या 1996 के अधिनियम के प्रावधानों के साथ कोई प्रतिकूलता नहीं है। असंगत उपचार प्रदान करना भी अस्वीकार्य है। ऐसे मामलों में प्रावधानों के टकराव का कोई सवाल ही नहीं है। यह उपलब्ध उपचारों में से किसी एक को चुनने के लिए खुला है।

8. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को स्वीकार करने से पहले, नियमों के नियम 5 के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करना उचित है जो 1996 के अधिनियम के साथ पठित 2006 के अधिनियम के तहत दी गई राशि की वसूली का प्रावधान करता है। नियम 5 यहाँ नीचे निकाला गया हैः

"5. भूमि राजस्व के बकाया के रूप में देय राशि की वसूलीः यदि कोई खरीदार स्वयं परिषद या किसी संस्था या केंद्र द्वारा दिए गए किसी डिक्री, पुरस्कार या अन्य आदेश को रद्द करने के लिए अधिनियम की धारा 19 के तहत कोई अपील दायर नहीं करता है या यदि ऐसी अपील खारिज कर दी जाती है, तो उस स्थिति में ऐसी डिक्री, पुरस्कार या आदेश संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा निष्पादित किया जाएगा और बकाया राशि को भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।

9. उपर्युक्त नियम 5 को 2006 के अधिनियम की धारा 30 के तहत नियम बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्ति को हटाने के लिए तैयार किया गया है जो राज्य सरकार को नियम बनाने में सक्षम बनाता है। धारा 30 यहाँ नीचे निकाली गई हैः

"30. राज्य सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति-(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है। (2) विशेष रूप से, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्ः

(क) सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद की संरचना, सदस्यों की रिक्तियों को भरने का तरीका और धारा 21 की उप-धारा (3) के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद के सदस्यों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

(ख) कोई अन्य मामला जो इस अधिनियम के तहत निर्धारित किया जाना है या किया जा सकता है।

(3) इस धारा के तहत बनाया गया नियम, इसे बनाए जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा, जहां दो सदन हैं, और जहां राज्य विधानमंडल का एक सदन है, उस सदन के समक्ष रखा जाएगा। धारा 30 राज्य सरकार को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने में सक्षम बनाती है। प्रकृति में शक्ति सामान्य और व्यापक है। इसमें कोई भी अन्य मामला शामिल है जो अधिनियम के तहत निर्धारित किया जाना है और किया जा सकता है, और नियम को राज्य विधानमंडल के सदन में रखा जाना आवश्यक है।

10. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लाभ के लिए 2006 का अधिनियम बनाया गया है। अधिनियम का उद्देश्य संवर्धन और विकास को सुविधाजनक बनाना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और उनसे जुड़े या प्रासंगिक मामलों का प्रावधान करना है। 2006 के अधिनियम की धारा 18 यहाँ नीचे निकाली गई हैः

"18. सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद का संदर्भ-(1) तत्काल लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, विवाद का कोई भी पक्ष धारा 17 के तहत देय किसी भी राशि के संबंध में सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद को निर्देश दे सकता है।

(2) उप-धारा (1) के तहत निर्देश प्राप्त होने पर, परिषद या तो स्वयं मामले में सुलह करेगी या सुलह करने के लिए ऐसी संस्था या केंद्र को निर्देश देकर वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं प्रदान करने वाली किसी संस्था या केंद्र की सहायता लेगी और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) की धारा 65 से 81 के प्रावधान ऐसे विवाद पर लागू होंगे जैसे कि सुलह उस अधिनियम के भाग III के तहत शुरू की गई थी।

(3) जहां उप-धारा (2) के तहत शुरू किया गया सुलह सफल नहीं होता है और पक्षकारों के बीच किसी भी समझौते के बिना समाप्त हो जाता है, परिषद या तो स्वयं विवाद को मध्यस्थता के लिए उठाएगी या इसे ऐसे मध्यस्थता के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं प्रदान करने वाली किसी संस्था या केंद्र को भेजेगी और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के प्रावधान तब विवादों पर लागू होंगे जैसे कि मध्यस्थता उस अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट मध्यस्थता समझौते के अनुसरण में थी।

(4) उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद या वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं प्रदान करने वाले केंद्र को अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित आपूर्तिकर्ता और भारत में कहीं भी स्थित खरीदार के बीच विवाद में इस धारा के तहत मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में कार्य करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

(5) इस धारा के तहत किए गए प्रत्येक संदर्भ का निर्णय ऐसा संदर्भ देने की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा "2006 के अधिनियम की धारा 18 (1) में प्रावधान है कि धारा 17 के तहत देय किसी भी राशि के संबंध में विवाद को सुविधा परिषद को भेजा जा सकता है। संदर्भ दिए जाने पर, परिषद स्वयं किसी भी संस्थान या एडीआर केंद्र की सहायता से सुलह कर सकती है। उस मामले में 1996 के अधिनियम की धारा 65 से 81 के प्रावधान लागू होंगे और यदि धारा 18 (2) के तहत सुलह सफल नहीं होती है, तो परिषद या तो स्वयं विवाद को मध्यस्थता के लिए उठाएगी या इसे किसी अन्य केंद्र या संस्था को मध्यस्थता के लिए भेजेगी और उसके बाद 1996 के अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

11. 1996 के अधिनियम की धारा 36 में प्रावधान है कि एक बार धारा 34 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने के लिए आवेदन दायर करने का समय समाप्त हो जाने के बाद, इसे सी. पी. सी. के प्रावधानों के अनुसार लागू किया जाएगा जैसे कि यह अदालत की डिक्री हो। धारा 36 (1) यहाँ नीचे निकाली गई हैः

"36. प्रवर्तन-(1) जहां धारा 34 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द करने के लिए आवेदन करने का समय समाप्त हो गया है, तो, उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, ऐसा पुरस्कार सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के प्रावधानों के अनुसार उसी तरह से लागू किया जाएगा जैसे कि यह अदालत की डिक्री थी। (2) जहां धारा 34 के तहत न्यायालय में मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द करने का आवेदन दायर किया गया है, वहां ऐसा आवेदन दायर करने से स्वयं उस पुरस्कार को अप्रवर्तनीय नहीं बनाया जाएगा, जब तक कि न्यायालय उस उद्देश्य के लिए किए गए एक अलग आवेदन पर, उप-धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार उक्त मध्यस्थता पुरस्कार के संचालन पर रोक लगाने का आदेश नहीं देता है। (3) माध्यस्थम अधिनिर्णय के प्रवर्तन पर रोक लगाने के लिए उप-धारा (2) के तहत आवेदन दायर करने पर,

न्यायालय, ऐसी शर्तों के अधीन, जो वह उचित समझे, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए ऐसे पुरस्कार के संचालन पर रोक लगा सकता हैः बशर्ते कि न्यायालय, धन के भुगतान के लिए मध्यस्थता पुरस्कार के मामले में रोक देने के लिए आवेदन पर विचार करते समय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के प्रावधानों के तहत धन डिक्री पर रोक लगाने के प्रावधानों का उचित सम्मान करेगा

इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2006 के अधिनियम की धारा 18 (3) में निहित प्रावधानों के आधार पर, 1996 के अधिनियम की धारा 36 में निहित प्रावधान स्पष्ट रूप से लागू होते हैं और सी. पी. सी. के तहत डिक्री के निष्पादन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मध्यस्थता पुरस्कार को निष्पादित करने की अनुमति है।

12. हालाँकि, तत्काल मामले में सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार को भूमि राजस्व के बकाया के रूप में राशि की वसूली के लिए नियमों के नियम 5 को लागू करने की अनुमति थी और क्या सी. पी. सी. के प्रावधानों के अनुसार एक डिक्री के रूप में मध्यस्थता पुरस्कार को निष्पादित करने के लिए 1996 के अधिनियम की धारा 36 में दिए गए उपचार के बावजूद, क्या 2006 के अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के तहत त्वरित उपचार प्रदान किया जा सकता था, जबकि उपचार प्रदान करते हुए राज्य ने अपनी शक्तियों को पार कर लिया है।

13. ऊपर निकाले गए 2006 के अधिनियम की धारा 30 स्पष्ट रूप से राज्य सरकार को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत करती है और शक्ति सामान्य है, जैसा कि धारा 30 (1), 30 (2) और 30 (2) (बी) को पढ़ने से स्पष्ट होता है। इस अधिनियम का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सुरक्षा प्रदान करना और उनके विकास को सुविधाजनक बनाना है। अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए नियम के नियम 5 के तहत त्वरित वसूली

तंत्र प्रदान किया गया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि मध्यस्थता पुरस्कार में दी गई राशि को भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नियम 5 1996 के अधिनियम की धारा 36 (1) में निहित प्रावधानों के साथ असंगत है जो एक डिक्री के रूप में सी. पी. सी. के आदेश 21 के तहत वसूली तंत्र प्रदान करता है, लेकिन ऐसे उपचार प्रदान करने के मामले में, यह विभिन्न उपायों को कानून बनाने के लिए खुला है जो असंगत हो सकते हैं। यह एक उपाय चुनने का सवाल है। राशि की वसूली के लिए एक उपाय का चुनाव पुरस्कार धारक की पसंद पर निर्भर करेगा। 1996 के अधिनियम की धारा 36 के साथ-साथ 2006 के नियमों के नियम 5 दोनों प्रावधानों का उद्देश्य अलग-अलग प्रक्रियाओं द्वारा राशि की वसूली करना है। प्रावधानों की मंशा समान है। निर्णय देनदार के प्रति कोई पूर्वाग्रह पैदा होने का कोई सवाल ही नहीं है।

14 बिहार राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड बनाम उनिया शंकर शरण और अन्य (1992) 4 एस. सी. सी. 196 में बिहार और उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम, 1935 की धारा 40 और 48 के तहत प्रदान किए गए उपचारों की बहुलता पर सवाल उठाया गया। दोनों प्रावधान एक मामले की ओर आकर्षित हो सकते हैं। यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 40 का अनुप्रयोग धारा 48 के प्रवर्तन को अपवर्जित नहीं करेगा। यह केवल एक सवाल है जिसमें प्रावधानों में से एक को चुना जाना है। इस न्यायालय ने आगे कहा है कि जब किसी क़ानून के तहत दो उपचार प्रदान किए जाते हैं, भले ही वे असंगत हों, तब तक वे तब तक लागू रहेंगे जब तक कि उनमें से एक को आवेदन के लिए नहीं चुना जाता है। भले ही दोनों उपचार असंगत हों, वे संबंधित व्यक्ति के लिए तब तक चुनना जारी रखते हैं, जब तक कि वह कार्रवाई शुरू करने के लिए उनमें से एक का चुनाव नहीं करता है। चूंकि धारा 40 के तहत कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, इसलिए इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 48 नुकसान की

वसूली के लिए अपीलार्थी के लिए उपलब्ध थी। बिहार राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (ऊपर) में इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्धारित किया हैः

"6. बहुवचन उपचारों की वैधता, यदि कानून के तहत उपलब्ध है, तो संदेह नहीं किया जा सकता है। यदि इस विषय पर किसी भी मानक पुस्तक की जांच की जाती है, तो यह पाया जाएगा कि बहस चुनाव के सिद्धांत के अनुप्रयोग के लिए निर्देशित है, जहां एक व्यक्ति के लिए दो या दो से अधिक उपाय उपलब्ध हैं। भले ही दोनों उपचार असंगत हों, वे संबंधित व्यक्ति के लिए चुनना जारी रखते हैं, जब तक कि वह उनमें से एक का चुनाव नहीं करता है, तदनुसार कार्रवाई शुरू करता है। वर्तमान मामले में ऐसी कोई समस्या नहीं है क्योंकि अपीलार्थी द्वारा धारा 40 के तहत कभी कोई कदम नहीं उठाया गया था। इसलिए, धारा 48 के प्रावधानों को नुकसान की वसूली के लिए अपीलार्थी के लिए उपलब्ध माना जाना चाहिए।

7. हमारा विचार है कि एक मामला जो अधिनियम की धारा 40 को आकर्षित कर सकता है, धारा 48 द्वारा शासित होता रहेगा, यदि आवश्यक शर्तों को पूरा किया जाता है, तो यह दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 के तहत उत्पन्न होने वाले प्रेम जीत कुमार बनाम सुरेंद्र गंडोत्रा मामले में इस न्यायालय के फैसले के अनुरूप है। दोनों अधिनियम समान हैं और बिहार अधिनियम की धारा 40 और 48 और दिल्ली अधिनियम की धारा 59 और 60 समान सामग्री में हैं। रिपोर्ट किए गए निर्णय ने पेंटाकोटा श्रीराकुलु बनाम सहकारी विपणन सोसायटी लिमिटेड में इस न्यायालय के पहले के फैसले का अनुसरण किया। हम तदनुसार मानते हैं कि उच्च न्यायालय यह मानने में त्रुटि कर रहा था कि बिहार अधिनियम की धारा 48 के प्रावधानों को वर्तमान मामले में लागू नहीं किया जा सकता था क्योंकि धारा 40 को आकर्षित किया गया था।

इस न्यायालय के उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट है कि बहुवचन उपचार का प्रावधान तब वैध होता है जब किसी व्यक्ति के लिए दो या दो से अधिक उपचार उपलब्ध होते हैं, भले ही वे असंगत हों, वे वैध होते हैं। उनमें से किसी एक को चुनना व्यक्ति का काम है और इस तरह का उपाय प्रदान करने में तिरस्कार का कोई सवाल ही नहीं है।

15. न्यायमूर्ति जी. पी. द्वारा "वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत" में। सिंह, 14 वीं संस्करण. असंगति और प्रतिकूलता के प्रश्न पर विचार करते हुए, यह देखा गया है कि सामंजस्यपूर्ण निर्माण को अपनाया जाना चाहिए और यह सिद्धांत कि विशेष प्रावधान सामान्य प्रावधान के अनुप्रयोग को बाहर करता है, तब लागू नहीं किया गया है जब दो प्रावधान उपचारों से संबंधित हैं क्योंकि बहुवचन उपचारों की वैधता पर संदेह नहीं किया जा सकता है, भले ही दोनों उपचार असंगत हों, अदालत को प्रावधानों में सामंजस्य स्थापित करना होगा। निम्नलिखित चर्चा की गई है:

"(b) असंगति और प्रतिकूलता से बचा जाना चाहिए; सामंजस्यपूर्ण निर्माण

यह पहले ही देखा जा चुका है कि एक क़ानून को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और अधिनियम के एक प्रावधान का अर्थ उसी अधिनियम के अन्य प्रावधानों के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए ताकि पूरे क़ानून को सुसंगत रूप से लागू किया जा सके। इस तरह के निर्माण में किसी धारा के भीतर या किसी धारा और क़ानून के अन्य हिस्सों के बीच किसी भी विसंगति या प्रतिकूलता से बचने का गुण है। यह अदालतों का कर्तव्य है कि वे एक ही अधिनियम की दो धाराओं के बीच "आमने-सामने टकराव" से बचें और "जब भी ऐसा करना संभव हो, उन प्रावधानों का अर्थ निकालें जो परस्पर विरोधी प्रतीत हों ताकि उनमें सामंजस्य हो"। तदनुसार, महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर योजना अधिनियम, 1966 के प्रावधानों को उच्चतम न्यायालय द्वारा एक साथ पढ़ा गया

और अधिनियम के उद्देश्य पर ध्यान दिया गया। अधिनियम को संघर्ष की स्थिति की परिकल्पना करने के लिए नहीं माना गया था, और इसलिए, अधिनियम के उन प्रावधानों को पढ़ने के लिए किनारों को इस्त्री करने की आवश्यकता थी जो थोड़े असंगत थे, ताकि उन सभी को अधिनियम के उद्देश्य के अनुरूप पढ़ा जा सके, जो कि व्यवस्थित और नियोजित विकास लाना है। यह हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए कि "संसद ने एक हाथ से वह दिया था जो उसने दूसरे हाथ से छीन लिया था।" कानून के एक खंड के प्रावधानों का उपयोग दूसरे के प्रावधानों को हराने के लिए तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उनके बीच सुलह करना असंभव न हो। यही नियम किसी धारा की उप-धाराओं के संबंध में भी लागू होता है। गजेंद्रगडकर के शब्दों में, जे। "उप-धाराओं को एक अभिन्न समग्र के भागों के रूप में और परस्पर निर्भर होने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए; यदि ऐसा करना उचित रूप से संभव है, तो उन्हें सामंजस्य स्थापित करने और घृणा से बचने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए।" जैसा कि जे. वेंकटरामा अय्यर ने कहा, "निर्माण का नियम अच्छी तरह से तय किया गया है कि जब किसी अधिनियम में दो प्रावधान हैं जिनका एक-दूसरे के साथ मिलान नहीं किया जा सकता है, तो उनकी व्याख्या इस तरह की जानी चाहिए कि यदि संभव हो तो दोनों को प्रभाव दिया जाना चाहिए। इसी को सामंजस्यपूर्ण निर्माण के नियम के रूप में जाना जाता है। यह, कि दोनों को प्रभाव दिया जाना चाहिए, नियम का सार है। इस प्रकार एक निर्माण जो प्रावधानों में से एक को "बेकार लकड़ी" या मृत पत्र "तक कम कर देता है, सामंजस्यपूर्ण निर्माण नहीं है। सामंजस्य स्थापित करने का अर्थ नष्ट करना नहीं है। ऐसे सभी मामलों में एक परिचित दृष्टिकोण यह पता लगाना है कि दो स्पष्ट रूप से परस्पर विरोधी प्रावधानों में से कौन सा अधिक सामान्य है और कौन सा अधिक विशिष्ट है और अधिक विशिष्ट को बाहर करने के लिए अधिक सामान्य का अर्थ लगाना है। सामान्य या विशेष प्रावधानों की सापेक्ष प्रकृति के बारे में प्रश्न का निर्धारण

आम तौर पर या विशेष रूप से विशेष स्थितियों में उनके अनुप्रयोग के क्षेत्र और सीमा के संदर्भ में किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत को मैक्सिम जनरलिया स्पेशलाइबस नॉन एलिमेंटेंट और जनरलिबस स्पिसिलिया एलिमेंटेंट में व्यक्त किया गया है। यदि किसी विशेष मामले पर कोई विशेष प्रावधान किया जाता है, तो उस मामले को सामान्य प्रावधान से बाहर रखा जाता है। अधिनियम के दो प्रावधानों के बीच संघर्ष को हल करने के अलावा, इस सिद्धांत का उपयोग अधिनियम के प्रावधान और अधिनियम के तहत बनाए गए नियम के बीच संघर्ष को हल करने के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा, इन सिद्धांतों को दो अलग-अलग अधिनियमों और दो अलग-अलग संविधान संशोधन अधिनियमों द्वारा जोड़े गए संविधान में दो प्रावधानों के बीच संघर्ष को हल करने और वैधानिक नियमों और वैधानिक आदेशों के निर्माण में भी लागू किया गया है। लेकिन यह सिद्धांत कि किसी मामले पर एक विशेष प्रावधान उस मामले पर एक सामान्य प्रावधान के अनुप्रयोग को बाहर करता है, तब लागू नहीं किया गया है जब दोनों प्रावधान उपचार से संबंधित हैं, बहुवचन उपचारों की वैधता पर संदेह नहीं किया जा सकता है। भले ही दोनों उपचार असंगत हों, वे संबंधित व्यक्ति के लिए चुनना जारी रखते हैं। जब तक वह उनमें से किसी एक को नहीं चुनता।

16 इस प्रकार, अपीलार्थी की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह निवेदन कि नियम 5 1996 के अधिनियम की धारा 36 के प्रावधानों के लिए असंगत और प्रतिकूल है, न्यायिक जांच का सामना नहीं कर सकता है और उपरोक्त तर्क के आधार पर खारिज किया जा सकता है।

17. इस न्यायालय ने मार्डिया केमिकल्स लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ (2004) 4 एस. सी. सी. 311 में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 (एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम) के प्रावधानों पर विचार करते हुए कहा है कि सुरक्षित ब्याज को अदालत के

हस्तक्षेप के बिना लागू किया जा सकता है। इस न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया है कि कानून के पक्ष में संवैधानिकता का अनुमान है। इस तरह के कानून के पक्ष में अनुमान पर विचार करते समय यह देखना आवश्यक होगा कि पीड़ित व्यक्ति को इस तरह के कानून के तहत शक्ति रखने वालों के हाथों एक उचित सौदा मिले। इस न्यायालय ने इस प्रश्न पर भी विचार किया कि क्या सरफेसी अधिनियम अनावश्यक था और क्षेत्र में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कारण ऋणों की वसूली अधिनियम, 993 के संचालन के आलोक में एक अवांछित कानून का अधिरोपण था। इस न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों की तुलनपत्रों पर ऋण और एन. पी. ए. के स्तर को देखते हुए, दीवानी अदालतों के माध्यम से ऋणों की वसूली के लिए लिया गया समय, आर्थिक प्रगति के लिए तरल और विलायक बैंकों और वित्तीय संस्थानों का महत्व, विशेष रूप से वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था में वित्तपोषण और ऋणों की वसूली के पुराने और पारंपरिक तरीकों को छोड़ने की आवश्यकता के साथ, और वांछित परिणाम लाने में 1993 के अधिनियम की विफलता, यह नहीं कहा जा सकता है कि ऋणों के प्रतिभूतिकरण और एन. पी. ए. की तेजी से वसूली के लिए साधन विकसित करने की दिशा में उठाया गया कदम आवश्यक नहीं था। इस न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया है कि निजी हित से अधिक सार्वजनिक हित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस प्रकार, दीवानी न्यायालय का सहारा लिए बिना, ठीक से वसूली के प्रावधान को बरकरार रखा गया। तत्काल मामले में, भूमि राजस्व के बकाया की वसूली का सहारा निर्णय प्रक्रिया के बाद लिया गया है जब मध्यस्थता पुरस्कार पारित किया गया था और जब 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत निर्धारित समय के भीतर इस पर आपत्ति नहीं की गई थी। इस प्रकार, प्रक्रिया को किसी भी तरह से अवैध या मनमाना नहीं कहा जा सकता है और इसे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि अपीलार्थी ने तर्क दिया है। उपरोक्त तर्क के

आधार पर यह स्पष्ट है कि सिविल प्रक्रिया संहिता एकमात्र उपाय नहीं हो सकती है। यह दीवानी न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना वसूली तंत्र को कानून बनाने के लिए खुला है।

18. अपीलार्थी की ओर से यह निवेदन किया गया था कि सी. पी. सी. का आदेश 21 विभिन्न नियमों के तहत अधिक सुरक्षा प्रदान करता है, जो ऊपर निर्दिष्ट हैं, एक निर्णय देनदार को मुकदमा दायर करने के लिए विभिन्न प्रकार की आपत्तियां उठाने के लिए और विभिन्न चरणों में भी आपत्ति करने का अधिकार है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सी. पी. सी. के तहत एक विस्तृत प्रक्रिया प्रदान की गई है। लेकिन अब तक यह सर्वविदित है कि एक डिक्री प्राप्त करने के बाद, सी. पी. सी. में एक डिक्री के निष्पादन के लिए निर्धारित एक विस्तृत प्रक्रिया के बेईमान निर्णय देनदारों द्वारा प्रावधानों के दुरुपयोग के कारण इसका त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करना अधिक कठिन हो गया है, जिसकी कभी परिकल्पना नहीं की गई थी। इस प्रकार, भूमि राजस्व के बकाया के रूप में त्वरित वसूली प्रदान करना, वास्तव में, आज की आवश्यकता थी और नियम 5 को त्वरित वसूली सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि छोटे, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को नुकसान न हो, सही ढंग से लागू किया गया है।

19. हम इस निवेदन में कोई बल नहीं पाते हैं कि भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली प्रक्रिया कठोर है। यह काफी उचित है और देय राशियों की वसूली के लिए विभिन्न अधिनियमों में प्रदान किया गया है। इस प्रक्रिया को किसी भी तरह से अवैध, मनमाना, कठिन या कठोर नहीं कहा जा सकता है।

20. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने कृषि बाजार समिति बनाम शालीमार केमिकल वर्क्स लिमिटेड (1997) 5 एस. सी. सी. 516 में निर्णय पर भरोसा रखा है जो इस प्रकार निर्धारित किया गया हैः

"24. प्रत्यायोजन की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 245 और अन्य सापेक्ष अनुच्छेदों के तहत समग्र रूप से विधायी शक्ति का एक घटक तत्व है और जब विधान मंडल जटिल सामाजिक-आर्थिक समस्याओं की चुनौती का सामना करने के लिए कानून बनाते हैं, तो वे अक्सर प्रशासनिक कानून के हिस्से के रूप में अधिनियमों द्वारा निर्धारित नीति को पूरा करने के लिए अपनी पसंद के प्रतिनिधियों को सहायक या सहायक शक्तियां सौंपना सुविधाजनक और आवश्यक पाते हैं। विधानमंडल को उक्त नीति को लागू करने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए विधायी नीति और सिद्धांत निर्धारित करना होगा, इससे पहले कि वह उस ओर से अपनी सहायक शक्तियों को सौंप दे (देखें वसंतलाल मगनभाई संजनवाला बनाम बॉम्बे और अन्य राज्य, [1961] 1 एस. सी. आर. 341। इस न्यायालय ने एक अन्य मामले में, दिल्ली नगर निगम बनाम बिड़ला कॉटन, स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, दिल्ली और एक अन्य मामले में, ए. एल. आर. (1968) एस. सी. 1232 के साथ-साथ दिल्ली कानून अधिनियम, 1912, अजमेर-मेरवाड़ा (कानूनों का विस्तार) अधिनियम, 1947 और भाग सी राज्य (कानून) अधिनियम, 1950, [1951] एस. सी. आर. 747 में एक पूर्व निर्णय में यह सिद्धांत निर्धारित किया है कि विधानमंडल को आवश्यक विधायी कार्यों को अपने हाथों में रखना चाहिए और जो सौंपा जा सकता है वह संबंधित अधिनियम के उद्देश्यों और उद्देश्यों को लागू करने के लिए आवश्यक अधीनस्थ कानून का कार्य है।

25. अविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, [1979] एल एस. सी. सी. 137 में, जे. कृष्ण अय्यर ने विधायी शक्ति के वैध प्रत्यायोजन के लिए निम्नलिखित परीक्षण निर्धारित किए। ये हैंः "

(1) विधायिका खुद को समाप्त नहीं कर सकतीः

(2) यह पूर्ण या आवश्यक विधायी कार्य को प्रत्यायोजित नहीं कर सकती है;

(3) भले ही प्रत्यायोजन हो, प्रत्यायोजित विधान पर संसदीय नियंत्रण एक संवैधानिक आवश्यकता के रूप में एक जीवित निरंतरता होनी चाहिए। इसे आगे इस प्रकार देखा गयाः "हालांकि एक आवश्यक विशेषता क्या है, इसे विस्तार से चित्रित नहीं किया जा सकता है, इसमें निश्चित रूप से नीति में परिवर्तन शामिल नहीं हो सकता है। विधायिका विधायी नीति का स्वामी है और यदि प्रतिनिधि नीति बदलने के लिए स्वतंत्र है तो यह विधायी शक्ति का ही दुरूपयोग हो सकता है।

26. इसलिए, जो सिद्धांत सामने आता है, वह यह है कि आवश्यक विधायी कार्य में विधायी नीति का निर्धारण शामिल है और विधानमंडल दूसरे के पक्ष में आवश्यक विधायी कार्य का त्याग नहीं कर सकता है। सहायक विधान बनाने की शक्ति विधानमंडल द्वारा अपनी पसंद के किसी अन्य निकाय को सौंपी जा सकती है, लेकिन विधानमंडल को प्रत्यायोजित करने से पहले, प्रतिनिधियों के मार्गदर्शन के लिए नीति और सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से या निहित रूप से स्पष्ट करना चाहिए। ये सिद्धांत कराधान कानूनों पर भी लागू होते हैं। इन सिद्धांतों का प्रभाव यह है कि सहायक नियम और विनियम बनाने के लिए अधिकृत प्रतिनिधि को अपने अधिकार के दायरे में काम करना होगा और वह अधिनियम या उसके तहत निर्धारित नीति के दायरे को व्यापक या संकुचित नहीं कर सकता है। यह नियम बनाने की आड़ में अधिनियम के दायरे में आने वाले क्षेत्र में कानून नहीं बना सकता है और इसे अधिनियम की नीति और उद्देश्य के कार्यान्वयन के तरीके तक ही सीमित रहना पड़ता है।

इस न्यायालय ने निर्धारित किया है कि विधायिका को उक्त नीति को लागू करने के लिए विधायी नीति निर्धारित करनी होगी। अधिनियम के उद्देश्यों और उद्देश्यों को लागू करने के लिए आवश्यक अधीनस्थ विधान का कार्य सौंपा जा सकता है। तत्काल मामले में धारा 30 के तहत प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करके, 2006 के अधिनियम के उद्देश्य की रक्षा की जा रही है। नियम का उद्देश्य उद्देश्य को लागू करना

है। यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिकार को पार कर दिया गया है और न ही यह कहा जा सकता है कि नियम बनाने की शक्ति की आड़ में अधिनियम का दायरा बढ़ाया या संकुचित किया गया है। दोनों प्रावधानों का उद्देश्य वसूली सुनिश्चित करना है।

21. डॉ. महाचंद्र प्रसाद सिंह बनाम अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद और अन्य मामलों में भी इस न्यायालय के एक फैसले पर रिलायंस को रखा गया है। (2004) 8 एस. सी. सी. 747 जिसमें इस न्यायालय ने कहा है कि प्रत्यायोजित विधान कुछ मौलिक कारकों के अधीन हैं। प्रतिनिधि का उद्देश्य विधायिका के उद्देश्य से अधिक व्यापक यात्रा करना नहीं है। एक प्रतिनिधि अधिनियम के दायरे या सामान्य संचालन का विस्तार नहीं कर सकता है लेकिन शक्ति सख्ती से सहायक है। इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्धारित किया है

"13. यह ध्यान दिया जा सकता है कि पैराग्राफ 8 के तहत, किसी सदन के अध्यक्ष या अध्यक्ष को दसवीं अनुसूची के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए नियम बनाने का अधिकार है। जिन नियमों को प्रत्यायोजित किया जा रहा है वे कुछ बुनियादी कारकों के अधीन हैं। प्रत्यायोजित विधान की अवधारणा का आधार मूल सिद्धांत है जिसे विधायिका प्रतिनिधि करती है क्योंकि यह हर विस्तार में अपनी इच्छा का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग नहीं कर सकती है। व्यवहार में यह केवल रूपरेखा निर्धारित कर सकता है। इसका मतलब है कि विधायिका का इरादा, जैसा कि रूपरेखा (जो कि सक्षम करने वाला अधिनियम है) में इंगित किया गया है, प्रत्यायोजित विधान के अर्थ और इसे बनाने की शक्ति की सीमा के लिए प्रमुख मार्गदर्शक होना चाहिए। शक्ति की वास्तविक सीमा प्रत्यायोजित विधान के कानूनी अर्थ को नियंत्रित करती है। प्रतिनिधि का उद्देश्य विधायिका के उद्देश्य से अधिक व्यापक यात्रा करना नहीं है। प्रतिनिधि का कार्य उस उद्देश्य की सेवा और प्रचार करना है, जबकि हर समय उसके प्रति सच्चा रहना है। यही प्राथमिक इरादे का नियम है। किसी अधिनियम द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति विनियमों द्वारा

प्राधिकरण को अधिनियम के दायरे या सामान्य संचालन का विस्तार करने में सक्षम नहीं बनाती है, लेकिन यह सख्ती से सहायक है। यह क़ानून में जो अधिनियमित किया गया है उसे लागू करने के लिए सहायक साधनों के प्रावधान को अधिकृत करेगा और इसके विशिष्ट प्रावधान के निष्पादन के लिए जो आकस्मिक है उसे शामिल करेगा। लेकिन ऐसी शक्ति अधिनियम के उद्देश्यों को व्यापक बनाने, उन्हें पूरा करने के नए और विभिन्न साधनों को जोड़ने या इसके उद्देश्यों से अलग होने या बदलने के प्रयासों का समर्थन नहीं करेगी। (फ्रांसिस बेनिओन की सांविधिक व्याख्या, तीसरी संस्करण में अध्याय "प्रत्यायोजित विधान" में धारा 59 देखें।) उपरोक्त सिद्धांत अधिक कठोरता के साथ लागू होगा जहां संवैधानिक प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में नियम बनाए गए हैं। ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जा सकता है जिसका प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों की विषय-वस्तु और विस्तार को बढ़ाने या सीमित करने का प्रभाव हो। इसी तरह, नियमों की व्याख्या उपरोक्त सिद्धांत के अनुरूप की जानी चाहिए।

हमारी राय में नियमों का नियम 5 एक उपचारात्मक प्रावधान होने के नाते सहायक है। यह अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त त्वरित उपचार प्रदान करने के लिए खुला है

22. रिलायंस को बी. के. श्रीनिवासन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य मामले में इस अदालत के एक फैसले पर भी रखा गया है। (1987) । एस. सी. सी. 618 जिसमें इस न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि अधीनस्थ विधान को प्रभावी होने के लिए किसी उपयुक्त तरीके से प्रकाशित या प्रख्यापित किया जाना चाहिए। जहां मूल क़ानून प्रकाशन या घोषणा के तरीके को निर्धारित करता है, उस तरीके का पालन किया जाना चाहिए। अधीनस्थ विधान के प्रकाशन का तरीका उचित होना चाहिए, जो आवश्यक है, तभी यह प्रभावी होगा। सवाल बिल्कुल अलग था। अन्यथा भी भूमि राजस्व की वसूली की प्रक्रिया काफी उचित है।

23. रिलायंस को पोषण सुधार अकादमी और अन्य बनाम भारतीय संघ आदि में रखा गया है। (2011) 8 एस. सी. सी. 274 जिसमें इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्धारित किया है।

"66. नियम बनाने की शक्ति सौंपने वाले क़ानून एक मानक पैटर्न का पालन करते हैं। संबंधित धारा में सबसे पहले "इस अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए" या "इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए" शब्दों का उपयोग करके प्रतिनिधि को सामान्य शब्दों में नियम बनाने की शक्ति प्रदान करने वाला एक प्रावधान होगा। इसके बाद आम तौर पर एक अन्य उप-धारा आती है जिसमें उन मामलों/क्षेत्रों की गणना की जाती है जिनके संबंध में विशिष्ट शक्ति "विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं" शब्दों का उपयोग करके प्रत्यायोजित की जाती है। ऐसे प्रावधानों की व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय ने कई निर्णयों में कहा है कि जहां सामान्य शब्दों में अधीनस्थ कानून बनाने की शक्ति प्रदान की जाती है, वहां मामलों/विषयों के बाद के विनिर्देशन को केवल उदाहरण के रूप में माना जाना चाहिए और सामान्य शक्ति के दायरे को सीमित नहीं करना चाहिए। नतीजतन, भले ही धारा 23 (1-ए) में विशिष्ट गणना किए गए विषय केंद्र सरकार को विवादित नियम (नियम 44-1) बनाने का अधिकार नहीं देते हैं, नियम बनाने को धारा 23 (1) के तहत केंद्र सरकार को प्रदत्त सामान्य शक्ति के संदर्भ में उचित ठहराया जा सकता है, बशर्ते कि नियम अधिनियम के दायरे से बाहर न जाए।

"लेकिन अधिनियम को लागू करने या लागू करने के लिए नियम या विनियम बनाने की सामान्य शक्ति भी सख्ती से सहायक प्रकृति की है और उस प्राधिकरण को सक्षम नहीं बना सकती है जिसे अधिनियम के सामान्य संचालन का दायरा बढ़ाने की शक्ति प्रदान की गई है। इसलिए, ऐसी शक्ति 'अधिनियम के उद्देश्यों को व्यापक बनाने,

उन्हें पूरा करने के लिए नए और अलग-अलग साधन जोड़ने, इसकी शर्तों से अलग होने या बदलने के प्रयासों का समर्थन नहीं करेगी'।

धारा 7 (iv) के तहत खाद्य प्राधिकरण की जनता के हित में खाद्य पदार्थ पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति और धारा 23 के तहत केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति के सवाल पर विचार करते हुए, यह माना गया कि केंद्र सरकार धारा 23 के तहत मानव उपभोग के लिए गैर-आयोडीनयुक्त नमक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती है। इस प्रकार, खाद्य मिलावट रोकथाम नियम, 1955 के नियम 44-1 के प्रावधान को अधिकार से बाहर माना गया। नियम 44-1 पूरी तरह से अधिनियम के दायरे से बाहर था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह एक नियम नहीं है जिसे लागू करने के लिए बनाया गया है या बनाया जाना आवश्यक है. अधिनियम के प्रावधान इसके उद्देश्य और योजना को ध्यान में रखते हुए जबकि तत्काल मामले में स्थिति संयुक्त है। इसलिए यह निर्णय अपीलार्थियों के लिए कोई मददगार नहीं है।

24. इसी तरह जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ और ए. एन. आर. बनाम डॉ. सुभाष चंद्र यादव और ए. एन. आर. में इस न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया गया है। (1988) 2 एससीसी 351। छावनी बोर्ड के एक कर्मचारी को दूसरे में स्थानांतरित करने के लिए नियम बनाए गए थे। यह अभिनिर्धारित किया गया कि सेवा हस्तांतरणीय नहीं थी क्योंकि ऐसा नियम 5 छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 280 (2) (सी) के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। तथ्यों पर मामले का कोई अनुप्रयोग नहीं है।

25. रिलायंस को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण बनाम के. डी. बाली एंड ए. एन. आर. (1988) 2 एस. सी. सी. 360 पर भी रखा गया है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि जब अधीनस्थ कानून मूल अधिनियम के साथ टकराव में है

तो उसे मूल क़ानून को रास्ता देना चाहिए। उपचारात्मक वैधानिक प्रावधानों के मामले में इस सिद्धांत का कोई उपयोग नहीं है क्योंकि असंगत उपचारों की बहुलता हमेशा प्रदान की जा सकती है और केवल एक ही उपाय चुना जाना है। अविंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य में। (1979) 1 एस. सी. सी. 137, यह निर्धारित किया गया है कि एक प्रतिनिधि विधानमंडल द्वारा निर्धारित नीति को बदलने के लिए स्वतंत्र नहीं है। उपरोक्त कारणों के आधार पर, निर्णय का समर्थन किए गए कारण के लिए कोई लाभ नहीं है

26. रिलायंस को सूरज मॉल मोहता एंड कंपनी बनाम ई. ए. वी. विश्वनाथ शास्त्री एंड अन्य पर भी रखा गया है। (1955) 1 एस. सी. आर. 448 जिसमें यह देखा गया है कि यदि विवादित अधिनियम द्वारा निपटाए गए व्यक्ति उन महत्वपूर्ण और मूल्यवान विशेषाधिकारों से वंचित हैं जो उन्हें अन्यथा भारतीय आयकर अधिनियम के तहत दिए जाते, तो उस स्थिति में यह कहना कोई बचाव नहीं है कि भेदभावपूर्ण प्रक्रिया भी न्याय के मार्ग को आगे बढ़ाती है। इस मामले का निर्णय आम समझदार व्यक्ति के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए न कि सरकार के दृष्टिकोण से। सामान्य समझदार व्यक्ति कहेगा, जब उसके खिलाफ भारी और आयकर की चोरी का गंभीर आरोप लगाया जाता है, तो एक समान व्यक्ति को भारतीय आयकर अधिनियम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का काफी लाभ क्यों होना चाहिए, जबकि दूसरे समान व्यक्ति को इससे वंचित किया जाना चाहिए। उक्त निर्णय के अनुपात का तत्काल मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, विचाराधीन प्रावधान उपचारात्मक है और नियम 5 द्वारा किसी भी महत्वपूर्ण या मूल्यवान विशेषाधिकार से वंचित नहीं किया जा रहा है। यह केवल प्रक्रियात्मक प्रावधान है और एक बार मध्यस्थ निर्णय पारित हो जाने के बाद निष्पादन की प्रक्रिया को सरल बनाने का इरादा रखता है।

27. रिलायंस को श्री मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड, मदुरै आदि बनाम श्री ए. वी. विश्वनाथ शास्त्री और अन्न पर भी रखा गया है। ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 13 जिसमें इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्धारित किया हैः

"3. अधिनियम द्वारा इसके प्रावधानों के तहत जांच करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया संक्षिप्त और कठोर प्रकृति की है। यह प्रक्रिया के सामान्य कानून से अलग है और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में इसके अधीन व्यक्तियों के लिए हानिकारक है और इस तरह भेदभावपूर्ण है। बख्शी हुई आय को पकड़ने के लिए आयकर अधिनियम की सामान्य प्रक्रिया और 1947 के अधिनियम 30 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया में पर्याप्त अंतर, इस न्यायालय द्वारा सुरा) मल मोहता बनाम श्री ए. वी. विश्वनाथ शास्त्री ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 545 में पूरी तरह से चर्चा की गई थी और यहां आगे चर्चा की आवश्यकता नहीं है।

उक्त मामले में, छूट गई आय को पकड़ने के लिए आयकर अधिनियम की सामान्य प्रक्रिया और आयकर (जांच आयोग) अधिनियम, 1947 के अधिनियम 30 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया में काफी अंतर था। किए गए वर्गीकरण को बिना किसी तर्क के अस्वीकार्य माना गया था। वर्तमान स्थिति में ऐसी स्थिति नहीं है। भूमि राजस्व के बकाया की वसूली के प्रक्रियात्मक प्रावधान को अपीलार्थियों के लिए प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता है। एक बार बकाया का निर्णय हो जाने के बाद अपीलार्थी से अपेक्षा की जाती थी कि वह 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत समय बीतने के बाद इसका सम्मान करेगा।

28. मगनलाल छगनलाल (पी) लिमिटेड बनाम ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम और अन्य में निर्णय। (1974) 2 एस. सी. सी. 402 का भी उल्लेख किया गया है जिसमें इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्धारित किया हैः

"14. संक्षेप में: जहां सामान्य प्रक्रिया से अलग अधिक कठोर प्रक्रिया का प्रावधान करने वाला कानून सामान्य प्रक्रिया द्वारा कवर किए गए पूरे क्षेत्र को शामिल करता है, जैसा कि अनवर सरकार के मामले और सुरा) मल्ल मोहता के मामले में मामलों के वर्ग के बारे में किसी भी दिशानिर्देश के बिना जिसमें किसी भी प्रक्रिया का सहारा लिया जाना है, कानून पर अनुच्छेद.14 का प्रभाव पड़ेगा। वहाँ भी, जैसा कि सुरा) मल्ल मोहता के मामले (ऊपर) में उल्लेख किया गया है, अपील के लिए एक प्रावधान दोष को ठीक कर सकता है। इसके अलावा, ऐसे मामलों में यदि प्रस्तावना और आसपास की परिस्थितियों के साथ-साथ क़ानून के प्रावधानों को स्वयं हलफनामों द्वारा समझाया और प्रवर्धित किया जाता है, तो आवश्यक दिशानिर्देशों का अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि सौराष्ट्र मामले (ऊपर) और ज्योति प्रसाद मामले (ऊपर) में क़ानून अनुच्छेद.14 से प्रभावित नहीं होगा।

फिर जहां क़ानून अपने आप में केवल एक वर्ग के मामलों को शामिल करता है जैसा कि हल्दर के मामले (ऊपर) और बाजोरिया के मामले (ऊपर) में क़ानून खराब नहीं होगा। तथ्य यह है कि ऐसे मामलों में कार्यपालिका यह चुनेगी कि विशेष प्रक्रिया के तहत किन मामलों की सुनवाई की जानी है, यह क़ानून की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा। इसलिए, यह तर्क कि केवल दो प्रक्रियाओं की उपलब्धता उनमें से एक, विशेष प्रक्रिया को दूषित कर देगी, कारण या प्राधिकरण द्वारा समर्थित नहीं है।

मगनलाल छगनलाल (ऊपर) में, इस न्यायालय ने सरकारी परिसरों में अनधिकृत कब्जाधारियों को बेदखल करने के लिए वैकल्पिक प्रक्रिया पर विचार किया; एक मुकदमे द्वारा और दूसरी संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा बॉम्बे नगर निगम अधिनियम, 1888 या बॉम्बे सरकार परिसर अधिनियम, 1955 के अध्याय V-A के तहत अधिक कठोर और कठिन होने का आरोप लगाया गया।

नियमों के नियम 5 के तहत परिकल्पित भूमि राजस्व की वसूली की प्रक्रिया को भेदभावपूर्ण नहीं कहा जा सकता है, यह काफी उचित प्रक्रिया है। इसे कठोर या कठोर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह काफी उचित प्रक्रिया है और यह अधिनियम के अधिदेश को आगे बढ़ाती है। नियम 5 और सी. पी. सी. के निष्पादन की प्रक्रिया के बीच के अंतर को अनुचित नहीं कहा जा सकता है ताकि भेदभाव की बुराई को आकर्षित किया जा सके।

29. नतीजतन, अपील बिना किसी योग्यता के पाई जाती है और इसे इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है। अपीलार्थी के बैंक खाते को डीफ्रीज करने के लिए 2017 का आई. ए. संख्या 6 दायर किया गया है। यदि अपीलार्थी ने नई वसूली प्रशस्ति पत्र के अनुसार रु. 5,29,58,937/- की राशि और ब्याज भी जमा किया है, तो राशि जमा होने की तारीख तक, यह संतुष्ट होने पर कि राशि इस तरह जमा की गई है, संबंधित तहसीलदार के लिए खाते को फ्रीज करने के लिए खुला रहेगा। छह सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वेलफेयर ट्रस्ट में जमा करने के लिए लागत की मात्रा Rs.50,000/- निर्धारित की गई है।

दिव्या पांडे याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक **मनीष शर्मा** द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है,एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।